क्षेत्रीय असंतुलन : समस्या एवं समाधान

○ अभिनय कुमार शर्मा

स्वातंत्र्योत्तर काल में निस्संदेह भारत ने क्रमवार विकास की सीढ़ियों पर अपना कदम रखा है परंतु भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की यदि विकास की तस्वीर अपने समक्ष रखें तो वह कुछ और ही है। भारत के कुछ राज्यों का पर्याप्त विकास हुआ, वहीं दूसरे राज्य विकास की दौड़ में काफी पीछे रहे

किसी भी संघीय शासन-प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु यह अति आवश्यक है कि संघ के सभी घटक अथवा इकाइयों का समुचित एवं समानांतर विकास हो। इस अवस्था में संघ का समग्र विकास एवं दीर्घायु होने की कामना अपेक्षित है। स्वातंत्र्योत्तर काल में निस्संदेह भारत ने क्रमवार विकास की सीढ़ियों पर अपना कदम रखा है। परंतु, अतीत से लेकर वर्तमान तक की यदि विकास की तस्वीर अपने समक्ष रखें तो वह कुछ और ही है। भारत के कुछ राज्यों का पर्याप्त विकास हुआ वहीं दूसरे राज्य विकास की दौड़ में काफी पीछे रहे। नाममात्र के विकास वाले क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या से अभिशप्त हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक

भारत के संदर्भ में असंतुलन शब्द प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त प्रतीत होता है। भौगोलिक स्वरूप, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना मुख्य रूप से क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। इन सबके अलावा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न भयावह स्थिति भी क्षेत्रीय असंतुलन को लाने के लिए उत्तरदायी है। कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या हो जाने से भी वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है। जैसे - बिहार का मिथिलांचल, उड़ीसा का कालाहांडी एवं बोलंगीर का क्षेत्र।

देश की राजनीतिक गतिविधियों का भी इसमें भारी योगदान है और वे भी क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म देने में पीछे नहीं हैं। इस समय देश दलगत राजनीति की बीमारी से ग्रस्त एवं त्रस्त है। यह देश के सतत और सुनियोजित विकास में बाधक है। उदाहरणार्थ - किसी निश्चित काल में केन्द्र सरकार अपने दल वाली राज्य सरकारों के विकास के प्रति अधिक जागरूक होती है न कि गैर-केन्द्रीय दल वाली राज्य सरकार वाले राज्य के प्रति। इसके चलते एक घातक स्थिति उत्पन्न होती है। यह है - अलगाववाद जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है।

क्षेत्रीय असंतुलन के कारण जहां उत्तर भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का अत्यधिक विकास हो गया, वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्य और जम्मू-कश्मीर केन्द्र सरकार की नीतियों को क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं।

इसके लिए योजना आयोग जैसी विशिष्ट संस्था भी उत्तरदायी है। योजना आयोग में बड़े राज्यों या यों कह सकते हैं कि केंद्रीय राजनीति में प्रभावी राज्यों के हितों तथा विकास का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि अनेक बार केंद्र सरकार के निर्माण